Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 15-12-2005

Participants : Khan Shri Sunil

an>

Title : Need to bring a comprehensive legislation providing for social security in unorganised sector.

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैं असंगठित शिल्प श्रमिकों के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

दिसम्बर में भारत के विभिन्न प्रान्तों के हजारों श्रमिक पार्लियामेंट स्ट्रीट में जमा हुए थे। इसलिए जमा हुए थे, क्योंकि असंगठित शिल्प श्रमिकों के लिए एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल सरकार लाये, उनकी यह डिमांड थी। क्योंकि जो निर्माणकर्मी हैं, जो बड़े-बड़े मकान बनाते हैं, लेकिन उनका कोई मकान नहीं है। अगर उनकी ज्यादा उम्र हो जाती है तो उनकी कौन देखभाल करेगा, इसलिए एक पी.एफ. का प्रावधान और पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। जैसे मटिया मजदूर हैं, जब उनका शरीर अच्छा होता है, उस समय वे कमाते हैं, बस दिन गुजारते हैं, बाकी समय कैसे गुजरेगा? जो हमारे ईंट भट्टे के श्रमिक हैं, जो बीड़ी मजदूर हैं, जो रिक्शापुलर हैं तो सारे भारत में ऐसे 37 करोड़ से भी ज्यादा असंगठित मजदूर हैं, लेकिन इनके लिए सोचने वाला कोई नहीं है।

हम लोग एम.पी. हैं, हमें भी पेंशन मिलती है। कोई डाक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर भी है, इनको पी.एफ. का लाभ भी मिलता है और पैंशन भी मिलती है। लेकिन आम जनता जिसको वोट देती है, जिनकी वजह से चुनकर पार्लियामेंट में आते हैं, वह हमारा गरीब किसान, खेतीहर मजदूर, खेत में काम करने वाला आदमी है, उनको तो यह सब नहीं मिलता है। हमारे पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत राहत हम लोग दे सके हैं, क्योंकि हमने किसी-किसी सलैक्टिड ट्रेड में पी.एफ. वहां चालू किया है।

हमारी सरकार से यह मांग है कि 37 करोड़ से ज्यादा जो खेतीहर मजदूर हैं, जो रिक्शापुलर हैं, ईंट भट्टे के श्रमिक हैं, जो निर्माणकर्मी हैं, इन सब लोगों के लिए एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल बनायें, ताकि उन लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिले, एजुकेशन मिले, हैल्थ की प्राब्लम दूर हो और जब ज्यादा उम्र हो जाये तो वह अपने बाल-बच्चे लेकर दाना-पानी उनके मुंह में दे सके।

मुझे जो कहना है, कह दिया, मैं समाप्त करता हूं।